



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1527]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 30, 2017/ज्येष्ठ 9, 1939

No. 1527]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 30, 2017/JYAISTHA 9, 1939

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

का.आ. 1723(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का रसायन और उर्वरक मंत्रालय का औषध विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) की केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम का प्रशासन कर रहा है।

और इस स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्र कहा गया है) को खोलने के लिए और संबंधित मूल्य शृंखला पणधारकों अर्थात् कैरिंग एंड फॉर्वाडिंग एजेंटों और वितरकों को नियुक्त करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र औषध उपक्रम ब्यूरो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) को नियुक्त किया है।

और इस स्कीम के अधीन केन्द्र स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों या स्थानीय सरकारी अभिकरणों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अधीन केन्द्रों के वैयक्तिक स्वामियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) दवाइयों की मासिक बिक्री पर आधारित होती है जिसमें भारत संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्बलित है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य) सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति से आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है और जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है, तो दिनांक 30 जून, 2017 तक आधार के लिए आवेदन करने की अपेक्षा होगी और ऐसे व्यक्ति का आधार नामांकन प्राप्त करने के लिए आधार नामांकन केन्द्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी। जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है और यदि ब्लाक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है विभाग से उसके क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय से या विभाग द्वारा स्वयं ही विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की अपेक्षा होगी।

परन्तु किसी व्यक्ति का आधार नियत किए जाने तक, ऐसे व्यक्ति को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन दी जाएंगी, अर्थात् :-

- (क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है, उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; या
- (ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए गए अनुरोध की प्रति; और
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज:
 - (i) मतदाता पहचान कार्ड; या
 - (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
 - (iii) पासपोर्ट; या
 - (iv) राशन पत्रिका; या
 - (v) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक
 - (vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अधिकारिक उसके शासकीय पत्र पर जारी पहचान प्रमाण पत्र जिसमें उसका फोटो हो; अथवा
 - (vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
 - (viii) किसान फोटो पासबुक; या
 - (ix) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन, फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधा रहित प्रसुविधा उपलब्ध कराने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं प्रबंध करेगा, अर्थात्:

(क) फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और उन्हें व्यक्तिगत सूचनाएं देकर इसका व्यापक प्रचार किया और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं कराया है तो उनको सलाह दी जाए कि वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करा लें। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे आसपास के क्षेत्र में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग से उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा होगी, तथा फायदाग्राहियों से उसका नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य अपेक्षित विवरण देकर विभाग के संबंधित पदधारियों या कार्यान्वयन अभिकरण या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रृत कराने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 35022/01/2017-आईसी]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

S.O. 1723(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers in the Government of India (hereinafter referred to as the Department) is administering the Central Sector Scheme of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (hereinafter referred to as the Scheme) with a view to achieving the objective of making available quality generic medicines at affordable prices to all;

And whereas, to achieve the objectives of the Scheme, the Department has appointed the Bureau of Pharma Public Sector Undertakings of India (hereinafter referred to as the Implementing Agency) to open Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendras (hereinafter referred to as the Kendras) and to appoint the related value chain stakeholders, namely Carrying and Forwarding Agents and Distributors.

And whereas, financial assistance is given to the Non-government organisations, individuals or local government agencies for setting up the Kendras under the Scheme. The incentive (hereinafter referred to as benefits) offered to the individual owners of the Kendras under the Scheme (hereinafter referred to as the beneficiaries) is based on monthly sales of medicines, which involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Any individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.06.2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by the Department itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) Any one of the following documents:

- (i) Voter Identity Card; or
- (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Ration Card; or
- (v) Bank or Post Office Passbook with Photo
- (vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on official letter head; or
- (vii) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- (viii) Kisan Photo Passbook; or
- (ix) Any other document as specified by the Department.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all required arrangements including the following, namely:-

- (a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.06.2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.
- (b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centers in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details, with the concerned officials of the Department or the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except in the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 35022/01/2017-IC]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.